GEO IAS
It's about quality

13 July 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | PIB | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Date: 13 July 2024

Important News Articles

1. पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा मॉस्को और वेस्ट दोनों को कैसे संदेश देती है?- इंडियन एक्सप्रेस
2. एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी- पीआईबी
3. केंद्र ने जम्मू-कश्मीर एलजी की प्रशासनिक भूमिका को व्यापक बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया- द हिंदू
4. प्रमुख क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता भारत बिल पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म- बिजनेस स्टैंडर्ड पर लाइव हो गए हैं
5. नाबार्ड ने ₹750 करोड़ का अनावरण किया। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि कोष- द हिंदू
6. चीन की तीसरी पूर्ण बैठक से पहले चाय की पत्तियाँ पढ़ना- द हिंदू
7. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ब्लू-इकोनॉमी पर भारत-नॉर्वे सहयोग की समीक्षा के लिए बैठक की- पीआईबी
8. जीएसटी प्रणाली सुधार पैनल में फेरबदल- द हिंदू

Editorials, Gists and Explainers

9. आदिवासी आवासीय विद्यालयों के लिए केंद्रीकृत भर्ती से भाषा, सांस्कृतिक बाधाएं पैदा होती हैं- द हिंदू
10. विश्व के जल संसाधनों के लिए खारी झीलें कोयला खदान में कैनरी क्यों हैं - डाउन टू अर्थ

Quick Look

1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड:
2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
3. राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर
4. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम
5. iCET

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा मॉस्को और वेस्ट दोनों को कैसे संदेश देती है?- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- शीत युद्ध
- रूस विरोधी ट्रांस-अटलांटिक सैन्य गठबंधन

समाचार:
- इस सप्ताह प्रधान मंत्री की वियना यात्रा जून 1983 के बाद किसी भारतीय प्रधान मंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी, जब इंदिरा गांधी ने देश की यात्रा की थी।
- मॉस्को में राष्ट्रपति से मुलाकात के तुरंत बाद वियना जाने का प्रधान मंत्री का निर्णय महत्वपूर्ण था - ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश है जो नाटो का हिस्सा नहीं है
- अमेरिका के नेतृत्व वाला रूस विरोधी ट्रांस-अटलांटिक सैन्य गठबंधन, जिसके 32 नेता इस सप्ताह वाशिंगटन डीसी में एकत्र हुए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- **व्यवसाय से स्वतंत्रता तक**: वियना का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। नाजी कब्जे ने मित्र देशों के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता की राह यहीं समाप्त नहीं होगी।
- **एक कूटनीतिक विजय: 1955** एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शीत युद्ध की रस्साकशी में फंसे ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रियाई राज्य संधि पर हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। विशेष रूप से, गुटनिरपेक्षता के समर्थक भारत ने स्विट्जरलैंड की तटस्थ स्थिति के समान, इस संधि को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **एक दीर्घकालिक बंधन:** भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध 1949 से चले आ रहे हैं, जो एक मजबूत रिश्ते की नींव रखते हैं।
- **स्थिरता पर केंद्रित भविष्य:** आज, दोनों देश पर्यावरण-अनुकूल आर्थिक उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाह रहे हैं।
- **साझा मूल्य, विविध हित:** ऑस्ट्रिया और भारत यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक मुद्दों की जटिलताओं से निपटते हैं, जबकि बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए रास्ते बनाते हैं।

2. एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी- पीआईबी

प्रासंगिकता: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत एवं अन्य उपाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- एसडीजी भारत
- नीति आयोग

समाचार:
- गरीबी उन्मूलन, सभ्य कार्य, आर्थिक विकास, जलवायु कार्रवाई और भूमि पर जीवन प्रदान करने के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण प्रगति।
- सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम-मुद्रा योजना, सौभाग्य, स्टार्ट-अप इंडिया आदि जैसे लक्षित हस्तक्षेपों का प्रभाव पड़ा और तेजी से सुधार हुआ।
- सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार दिखाया है
- 2023-24 के लिए देश का समग्र एसडीजी स्कोर 71 है, जो 2020-21 में 66 और 2018 में 57 से महत्वपूर्ण सुधार है।
- 2023-24 में राज्यों का स्कोर 57 से 79 तक है, जो वर्ष 2018 की 42 से 69 की तुलना में काफी सुधार दर्शाता है।
- **लक्ष्य 1** (गरीबी नहीं), 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास), 13 (जलवायु कार्रवाई) और 15 (भूमि पर जीवन) में महत्वपूर्ण प्रगति

- **लक्ष्य 13** (जलवायु कार्रवाई) ने 2020-21 में 54 से 2023-24 में 67 तक स्कोर में उच्चतम वृद्धि दर्ज की, इसके बाद लक्ष्य 1 (गरीबी नहीं) 60 से 72 तक पहुंच गया।
- 2018 और 2023-24 के बीच, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश (स्कोर में 25 की वृद्धि) हैं, इसके बाद जम्मू-कश्मीर (21), उत्तराखंड (19), सिक्किम (18), हरियाणा (17), असम, त्रिपुरा और पंजाब (16) हैं। प्रत्येक), मध्य प्रदेश और ओडिशा (15 प्रत्येक)
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) से जुड़े **113 संकेतकों** पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है।
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है। 16 एसडीजी में उसके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए लक्ष्य-वार स्कोर से समग्र राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्कोर या समग्र स्कोर तैयार किए जाते हैं।
- ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं, और यदि कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर हासिल करता है, तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का स्कोर जितना अधिक होगा, लक्ष्य तक तय की गई दूरी उतनी ही अधिक होगी।
- सतत विकास पर 2030 एजेंडा को अपनाने के बाद से एसडीजी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता नीति आयोग के नेतृत्व में एसडीजी स्थानीयकरण पर ठोस प्रयासों में परिलक्षित होती है, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करता है।
- नीति आयोग के पास देश में एसडीजी को अपनाने और निगरानी करने और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दोहरा काम है।

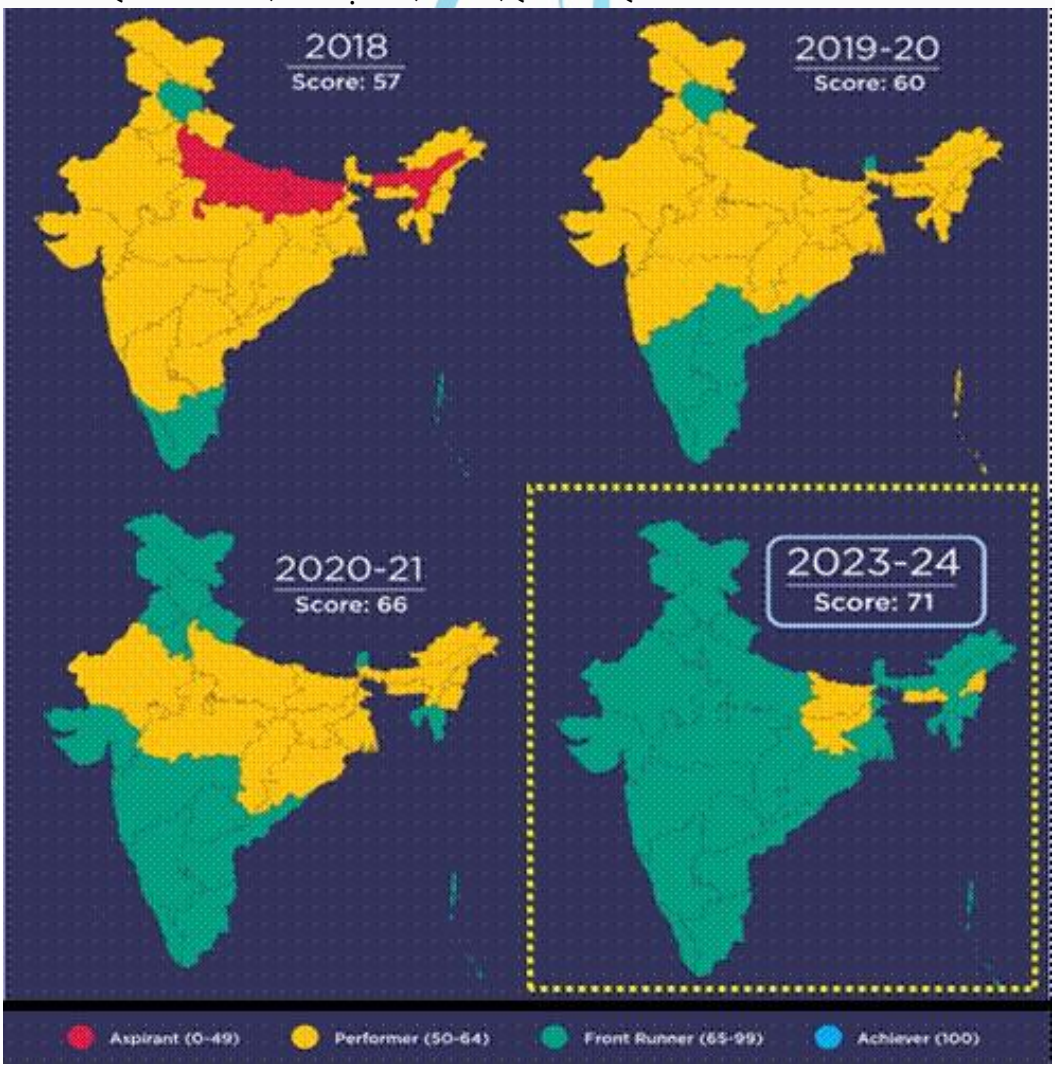

3. केंद्र ने जम्मू-कश्मीर एलजी की प्रशासनिक भूमिका को व्यापक बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- विशेष श्रेणी राज्य
- निर्वाचन आयोग

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

समाचार:
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने व्यापार नियमों के लेनदेन में संशोधन करके जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक भूमिका का दायरा बढ़ा दिया है।
- संशोधन पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) से संबंधित मामलों में एलजी को अधिक अधिकार देता है, जिसके लिए वित्त विभाग की पूर्व सहमति और उनके स्थानांतरण और पोस्टिंग की भी आवश्यकता होती है।

मुख्य बिंदु:
- महाधिवक्ता, कानून अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में कोई भी प्रस्ताव और अभियोजन की मंजूरी देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में प्रस्ताव पहले एलजी के समक्ष रखा जाएगा।
- 5 अगस्त, 2019 को, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया और पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया:
    - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, बिना विधानसभा के मौजूद हैं
- जून 2018 से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासन के अधीन है।
- सरकार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है.
- गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें एलजी की भूमिका को परिभाषित करने वाली नई धाराएं शामिल की गईं।
- अधिनियम के तहत उपराज्यपाल के विवेक का प्रयोग करने के लिए 'पुलिस', 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'अखिल भारतीय सेवा' और 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव को तब तक सहमति या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा गया है, "अधिसूचना में कहा गया है।
- इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है, "कानून, न्याय और संसदीय मामलों का विभाग अदालती कार्यवाही में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा। सचिव और मुख्यमंत्री।"
- इसमें कहा गया है कि अभियोजन की मंजूरी देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।
- जेल, अभियोजन निदेशालय और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से जुड़े सभी मामले भी एलजी को सौंपे जाने हैं।

सामान्य अध्ययन III

4. प्रमुख क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता भारत बिल पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म- बिजनेस स्टैंडर्ड पर लाइव हो गए हैं

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत बिल भुगतान प्रणाली

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों की योजना, जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:
- सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक सहित प्रमुख क्रेडिट जारीकर्ताओं ने तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने सिस्टम को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के साथ एकीकृत किया है।

मुख्य बिंदु

- बीबीपीएस वेबसाइट के अनुसार, वर्तमान में एक्सिस बैंक, चौथा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता, इंडियन ओवरसीज बैंक और यस बैंक अपने सिस्टम को एकीकृत करने की प्रक्रिया में हैं और जल्द ही प्लेटफॉर्म पर लाइव होने की उम्मीद है।
- वर्तमान में, 15 प्रमुख जारीकर्ता प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, जिनमें आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक, बीओबी कार्ड और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।
- अब देश में 30 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता हैं।
- बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर रहने वाले जारीकर्ता लगभग 80-85 प्रतिशत क्रेडिट ग्राहक हैं।
- संक्षेप में, अधिकांश लेनदेन अब बीबीपीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधित किए जा रहे हैं
- शेष क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता वर्तमान में अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं और जब भी वे तैयार होंगे, बीबीपीएस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत हो जाएंगे।
- सूत्र ने कहा, हालांकि इसकी कोई निश्चित समयसीमा नहीं है कि ये छोटे खिलाड़ी कब लाइव होंगे, लेकिन अंततः इन सभी को लाइव होना ही होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आदेश दिया था कि 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड भुगतान बीबीपीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधित किए जाने चाहिए।
- इस कदम का उद्देश्य बिल भुगतान प्रक्रिया को केंद्रीकृत करना और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इससे पहले, कुछ तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले बीबीपीएस में एकीकृत बैंकों के लिए विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की सुविधा का विकल्प चुना था। यह आरबीआई के आदेश का अनुपालन करना था।
- हालांकि क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं के बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर लाइव होने में देरी हुई है, लेकिन ग्राहकों के बीच व्यवधान व्यापक नहीं हुआ है क्योंकि उपयोगकर्ताओं के पास अपना बकाया चुकाने के लिए कई विकल्प हैं।
- वर्तमान में, क्रेडिट, पेटीएम, फोनपे या अमेज़ॅन पे जैसे तृतीय-पक्ष ऐप क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं को धन हस्तांतरित करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या अन्य भुगतान विधियों का उपयोग करते हैं।

5. नाबार्ड ने ₹750 करोड़ का अनावरण किया। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि कोष- द हिंदू

प्रासंगिकता: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे;

प्रीलिम्स टेकअवे
- नाबार्ड
- कृषि निधि

समाचार:

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कहा कि उसकी शाखा ने स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए 750 करोड़ रुपये का कृषि कोष लॉन्च किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- 'एग्री-श्योर' नामक फंड की घोषणा नाबार्ड की सहायक कंपनी एनएबी वेंचर्स (NAB VENTURES) द्वारा की गई है, जिसमें 750 करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष है, जिसमें नाबार्ड और कृषि मंत्रालय प्रत्येक से 250 करोड़ रुपये और अन्य संस्थानों से 250 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- इस फंड का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीन, प्रौद्योगिकी-संचालित, उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देना है।
- नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएबी वेंचर्स द्वारा प्रबंधित, इस फंड को 25 करोड़ रुपये तक के निवेश आकार वाले लगभग 85 कृषि स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए संरचित किया गया है।
- यह फंड सेक्टर-विशिष्ट, सेक्टर-अज्ञेयवादी और ऋण वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश के साथ-साथ स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष इक्विटी सहायता प्रदान करेगा।

6. चीन की तीसरी पूर्ण बैठक से पहले चाय की पत्तियाँ पढ़ना- द हिंदू

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:
- पश्चिम में टिप्पणीकारों के अनुसार कहा जा रहा है कि अब शीत युद्ध के बाद की दुनिया की गुलाबी दृष्टि (the rosy vision) से आगे बढ़ने का समय आ गया है,
- मॉस्को और बीजिंग से अब नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर जिम्मेदार हितधारक बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती है

चीन की तीसरी पूर्ण बैठक: अगले दशक के लिए मंच तैयार करना
- **पीछे मुड़कर देखें, आगे की ओर देखें:** चीन में तीसरा पूर्ण सत्र प्रमुख नीति चौकियों के रूप में कार्य करता है, जो अगले आधे दशक या उससे अधिक के लिए आर्थिक दिशा तय करता है। देंग जियाओपिंग के नेतृत्व में 1978 का प्लेनम सुधार और खुलेपन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में सामने आया।
- **चुनौतियाँ और अवसर:** चीन की बढ़ती आबादी, घटती कार्यबल और बढ़ता कर्ज महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है। आगामी तीसरा प्लेनम इन मुद्दों को संबोधित करने और आर्थिक विकास को फिर से शुरू करने के लिए सुधारों का अनावरण कर सकता है।
- **दुनिया देख रही है:** वैश्विक पर्यवेक्षक चीन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले साहसिक सुधारों की उम्मीद में प्रत्याशा के साथ इंतजार कर रहे हैं। हालाँकि, वर्तमान नेतृत्व की प्रयोग करने की इच्छा पर संदेह बना हुआ है।
- **विश्व मंच पर चीन का रुख:** पश्चिमी टिप्पणीकारों को उम्मीद है कि चीन अपनी आक्रामक रणनीति जारी रखेगा, जिसमें सूचना युद्ध, सैन्य युद्धाभ्यास और ताइवान पर दबाव शामिल है।
- **विश्व व्यवस्था को आकार देना:** चीन की वैश्विक पहल - जीडीआई, जीएसआई और जीसीआई - उसके मूल्यों और सुरक्षा चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश करती हैं।
- **एक जटिल रिश्ते को आगे बढ़ाना:** एशियाई देशों को चीनी सांस्कृतिक प्रभाव और चीन से राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की बढ़ती भावना के संयोजन का सामना करना पड़ सकता है।

7. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ब्लू-इकोनॉमी पर भारत-नॉर्वे सहयोग की समीक्षा के लिए बैठक की- पीआईबी

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत आर्कटिक मिशन
- अंटार्कटिक मिशन

समाचार:
- केंद्रीय मंत्री ने भारत में नॉर्वे के राजदूत के साथ ब्लू-इकोनॉमी पर भारत-नॉर्वे सहयोग की समीक्षा के लिए एक बैठक की
- मंत्री ने '**भारत-नॉर्वे एकीकृत महासागर प्रबंधन और अनुसंधान पहल**' को भी याद किया और कहा कि हमें अपने सहयोग को और गहरा करने की जरूरत है।
- उन्होंने राजदूत के साथ यह भी साझा किया कि भारत तीन भारतीयों को गहरे समुद्र में भेजकर एक गहरे समुद्र मिशन को अंजाम दे रहा है जो खनिज अन्वेषण और समुद्री खनन में अवसरों का क्षितिज खोलेगा।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा वर्णित इस क्षेत्र में गति बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व ने भारत की समुद्री और महासागरीय खोज की यात्रा को सक्षम बनाया।
- उन्होंने यह भी कहा, "नीली अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा को बढ़ावा देगी।" उन्होंने भारत की प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों के रूप में आर्कटिक में IndARC की तैनाती पर प्रकाश डाला - ध्रुवीय जल में भारत की पहली उप-सतह दलदली वेधशाला, जो नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच लगभग आधी है।
- भारत में नॉर्वे के राजदूत ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत परियोजनाओं के लिए बढ़ते सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मंत्री के प्रयासों की सराहना की।
- राजदूत ने अपने प्रधान मंत्री की टिप्पणियों को याद किया कि जहां तक वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना का सवाल है, भारत और नॉर्वे अंटार्कटिका में पड़ोसी हैं।

- मंत्री ने उल्लेख किया कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक में ध्रुवीय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग के लिए राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) और नॉर्वेजियन ध्रुवीय संस्थान (एनपीआई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने समुद्री स्थानिक योजना (एमएसपी) के लिए भारत और नॉर्वे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मसौदा ढांचे को याद किया।
- आगे बढ़ते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और नॉर्वे दोनों फ्रांस में 2025 में महासागरों पर आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनओसी-3) के लिए तत्पर हैं।

8. जीएसटी प्रणाली सुधार पैनल में फेरबदल- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- जीएसटी
- अनुच्छेद 279ए(1)

समाचार:
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने एक मंत्रिस्तरीय समूह का पुनर्गठन किया है, जिसे राजस्व चोरी के संभावित स्रोतों की पहचान करने, केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार करने और अप्रत्यक्ष कर को लागू करने के लिए आईटी प्रणालियों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।

मुख्य बिंदु:
- ये परिवर्तन आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों से नए मंत्रियों को लाने के लिए प्रभावित हुए हैं, जहां हाल के महीनों में नई सरकारें स्थापित हुई हैं, साथ ही हरियाणा के प्रतिनिधियों को भी प्रतिस्थापित किया गया है।
- इस प्रमुख जीएसटी पैनल का पुनर्गठन परिषद द्वारा जीएसटी दर संरचना और इसकी कर दरों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश करने वाले मंत्री समूह के पुनर्गठन के तुरंत बाद हुआ है।
- परिषद, जो लगभग नौ महीने के अंतराल के बाद जून के अंत में मिली थी, ने इस जीओएम द्वारा अब तक की गई प्रगति का जायजा लेने और अपनी अगली बैठक में बहुप्रतीक्षित जीएसटी दर पुनर्गठन अभ्यास के रोडमैप पर चर्चा करने की योजना बनाई है।
- परिषद द्वारा आईटी चुनौतियों और राजस्व जुटाने से निपटने के लिए दो अलग-अलग मंत्रियों के समूहों (जीओएम) को एकजुट करने का निर्णय लेने के बाद 2021 के अंत में गठित, जीएसटी प्रणाली सुधारों पर जीओएम को चौथी बार पुनर्गठित किया गया था।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

9. आदिवासी आवासीय विद्यालयों के लिए केंद्रीकृत भर्ती से भाषा, सांस्कृतिक बाधाएं पैदा होती हैं- द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रसंग:
- हिंदी भाषी राज्यों से बड़ी संख्या में भर्ती किए गए कर्मचारी दक्षिणी राज्यों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में पोस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, जहां की भाषा, भोजन और संस्कृति उनके लिए अपरिचित है।

मुख्य प्रसंग:
- हालांकि केंद्रीय अधिकारी बताते हैं कि देश में कहीं भी तैनात होने की इच्छा नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की आवश्यकता का हिस्सा थी,
- बड़ी चिंता यह हो सकती है कि स्थानीय भाषा और संस्कृति से अपरिचित शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे आदिवासी छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
- पिछले साल तक, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रमुख एकलव्य स्कूलों के लिए कर्मचारियों की भर्ती राज्य अधिकारियों द्वारा की जाती थी।
- हालाँकि, संसद के 2023 के बजट सत्र में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जिम्मेदारी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) को सौंपी जा रही है, जिसे अब देश भर के 400 से अधिक एकलव्य स्कूलों में 38,000 पदों पर स्टाफ का काम दिया गया है। देश।

स्टाफ की कमी

- अधिकारियों ने कहा कि भर्ती का केंद्रीकरण ईएमआरएस प्रणाली में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने और राज्यों में भर्ती नियमों को मानकीकृत करने के लिए था, जिन्होंने पहले अलग-अलग मानदंडों का इस्तेमाल किया था और अपने राज्य विधानों के अनुसार आरक्षण कोटा लागू किया था।
- सरकारी सूत्रों ने कहा कि बुनियादी हिंदी भाषा दक्षता की आवश्यकता के बारे में "कुछ भी असामान्य नहीं" है क्योंकि यह जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों की भर्ती के लिए भी अनिवार्य है।
- हालांकि, केवी के विपरीत, जहां छात्र देश भर से आते हैं क्योंकि वे अक्सर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवार के सदस्य होते हैं, एकलव्य स्कूलों में अधिकांश आदिवासी छात्रों को उन शिक्षकों से लाभ होगा जो उनके स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों को समझते हैं।
- "मुद्दा यह है कि विशेष रूप से ईएमआरएस के लिए, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को उनके स्थानीय समुदायों के भीतर से काम पर रखा जाना आगे बढ़ने का स्पष्ट तरीका है।
- इन समुदायों में बहुत विशिष्ट संदर्भ हैं जिनके तहत सीखने को अनुकूल बनाया जा सकता है और ऐसे शिक्षकों को रखने से स्वाभाविक रूप से मदद मिलेगी जो उस संदर्भ को समझते हैं।
- "कुछ ईएमआरएस बहुत दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनके बहुत विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ हैं। ऐसा कुछ होने से उनकी पढ़ाई पर ही असर पड़ेगा।
- तेलुगु या मराठी संदर्भ में एक बच्चे से उन शिक्षकों के साथ तालमेल बिठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। यदि गैर-हिन्दी भाषी शिक्षक हिन्दी भाषी क्षेत्रों में चले जायेंगे तो इसका भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा।
- भर्ती किए गए कर्मचारियों को दो साल के भीतर स्थानीय भाषा सीखने के लिए कहा गया है, और "उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रक्रिया में कुछ हद तक सहयोग किया जाएगा"।

10. विश्व के जल संसाधनों के लिए खारी झीलें कोयला खदान में कैनरी क्यों हैं - डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- क्षेत्रीय मानवीय गतिविधियों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में अधिक स्थायी परिवर्तन आम हो गए हैं।

मुख्य प्रसंग:

- जब अंतर्देशीय सतही जल निकायों की बात आती है, तो खारी झीलें अद्वितीय होती हैं।
- वे दुनिया भर की सभी झीलों का 44 प्रतिशत बनाते हैं और अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं।
- इन झीलों का अस्तित्व नदी बेसिन के जल इनपुट (वर्षा और प्रवाह) और आउटपुट (वाष्पीकरण और रिसाव) के बीच एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है।
- किसी झील के खारा हो जाने का कारण अक्सर यह होता है कि उसमें जल प्रवाह का एक सुसंगत आउटलेट नहीं होता है, जिससे पानी के प्रवाह से घुले हुए लवण जमा हो जाते हैं।
- खारी झीलों का जल स्तर प्राकृतिक रूप से अस्थिर होता है और ये झीलें आमतौर पर किसी भी गड़बड़ी के प्रति संवेदनशील होती हैं।
- यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता खारे पानी की झीलों को मीठे पानी की झीलों की तुलना में प्राकृतिक और मानव-जनित कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
- खारी झील में परिवर्तन का मुख्य कारण उसके जल संतुलन में गड़बड़ी है।
- ये प्राकृतिक या मानव-प्रेरित कारकों का परिणाम हो सकते हैं जो स्थानीय हैं, जैसे सूखा, प्रदूषण, और अपस्ट्रीम जल विचलन, या वैश्विक, जैसे जलवायु परिवर्तन, घटती वर्षा और बढ़ता तापमान।
- बदलती परिस्थितियों के प्रति खारी झीलों की तीव्र प्रतिक्रिया इन झीलों को जल संसाधनों की क्षेत्रीय और संभावित वैश्विक स्थिति को विश्वसनीय रूप से प्रतिबिंबित करने और जल संतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाती है।
- आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की कई खारी झीलें तेजी से सिकुड़ रही हैं, जो क्षेत्रीय जल संसाधनों की स्थिरता के बारे में एक बड़ी चेतावनी है।

खारी झीलें कैसे बदल रही हैं?

- खारी झीलों में हमेशा उतार-चढ़ाव होता रहा है।
- अधिकांश झीलें सिकुड़ रही हैं और उनके पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है।
- हालाँकि, आर्कटिक और तिब्बती पठार के पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों में, गर्म जलवायु में बर्फ के पिघलने के कारण कुछ नमक झीलों का विस्तार हुआ है।
- खारी झीलों में परिवर्तन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करता है।
- वे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और उद्योगों को खतरे में डाल सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं और व्यापक सामाजिक-आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- ईरान की उर्मिया झील इसका अच्छा उदाहरण है।
- कुछ दशक पहले तक, उर्मिया झील दुनिया की सबसे बड़ी खारी झीलों में से एक थी, लेकिन अस्थिर मानवीय गतिविधियों के कारण यह तेजी से सिकुड़ गई।
- परिणामी समस्याओं में पर्यटन में गिरावट, धूल और नमक के तूफान, कृषि उत्पादकता में गिरावट और जैव विविधता का नुकसान शामिल है।
- अरल सागर, जो कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय था, एक और दुखद उदाहरण है।
- 1960 के दशक के बाद से यह क्षेत्र में खराब योजनाबद्ध सिंचाई विकास के कारण अपने पूर्व आकार के एक अंश तक सिकुड़ गया है।
- परिणाम विनाशकारी रहे हैं. अनेक प्रयासों के बावजूद भी झील को उसका पूर्व गौरव लौटाना संभव नहीं हो सका है।

हमारी प्राकृतिक पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ

- खारी झीलें, कोयला खनिकों को खतरनाक रूप से खराब वायु गुणवत्ता की पूर्व चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैनरी की तरह, हमारे जल संसाधनों के स्वास्थ्य की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- इस सादृश्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हमें सबसे पहले भूमिगत खदानों की गहराई में जाना होगा जहां कोयला खनिक एक छिपे हुए खतरे से जूझ रहे थे: **कार्बन मोनोऑक्साइड।**
- यह गैस बिना किसी चेतावनी के चुपचाप जमा हो सकती है, जिससे खनिकों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।
- खनिकों ने एक अनोखा समाधान निकाला: कैनरी। ये छोटे पक्षी, अपनी तेज़ साँस लेने की दर, छोटे आकार और तेज़ चयापचय के साथ, खतरे के छोटे डिटेक्टर थे।
- जब कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तो कैनरी संकट के लक्षण दिखाने वाले पहले व्यक्ति होंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, खनिकों को खाली करने की महत्वपूर्ण चेतावनी दी जाएगी।
- प्राकृतिक दुनिया हमें अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि प्रदान करती रहती है। खारी झीलें, अपने जटिल पारिस्थितिक तंत्र और अनूठी विशेषताओं के साथ, प्रकृति की पूर्व-चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं।
- जिस तरह कनारी कोयला खदानों में छिपे खतरों का संकेत देते हैं, उसी तरह खारे झीलों का व्यवहार हमें हमारे जल संसाधनों के साथ उभरते मुद्दों के प्रति सचेत कर सकता है।

बड़ी तस्वीर हमारा ध्यान आकर्षित करती है

- निःसंदेह, जब झीलें सिकुड़ रही हों तो कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, चाहे संरक्षण प्रयासों के माध्यम से या पुनर्स्थापना परियोजनाओं के माध्यम से।
- लेकिन हमें बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह उस खनिक की तरह होगा जो संकटग्रस्त कैनरी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जबकि यह अधिक गंभीर समस्या का संकेत है।
- असली चुनौती केवल पक्षियों को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने के बजाय खदानों में खराब वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की तरह, मूल कारण की जांच करने में है।

GEO IAS
It's about quality

फैक्ट फटाफट

1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

- AWBI केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय है।
- इसकी कानूनी संरचना **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम**, 1960 से प्राप्त हुई है।
- इसकी शुरुआत स्वर्गीय श्रीमती के नेतृत्व में की गई थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, प्रसिद्ध मानवतावादी।
- यह इस बात पर नियम बनाता है कि हर जगह जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जानवरों को अनुचित रूप से परेशान या प्रताड़ित न किया जाए, इसने अक्सर सख्त कानून बनाने के लिए भी मुकदमा चलाया है।
- बोर्ड में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और सांसदों के साथ-साथ कई सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व है।
- बोर्ड में 28 सदस्य हैं। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है।

2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

- यह चुने हुए आधार वर्ष के संदर्भ में एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन के व्यवहार में रुझान के मापन के लिए आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतकों में से एक है।
- यह पिछले वर्ष की तुलना में एक निर्दिष्ट वर्ष के दौरान उद्योगों के क्षेत्र में भौतिक उत्पादन के सापेक्ष परिवर्तन को इंगित करता है।
- इसकी गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। आधार वर्ष को हमेशा 100 का मान दिया जाता है।
- भारत में IIP श्रृंखला के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। इसलिए, यदि वर्तमान आईआईपी 116 पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि आधार वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि हुई है।

3. राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

- एनएमएचसी का निर्माण बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत गुजरात के लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में किया जा रहा है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना, एडुटेनमेंट दृष्टिकोण का उपयोग करना और नवीनतम तकनीक को शामिल करना है।
- एनएमएचसी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर और एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनने के लिए तैयार है।
- यह आगंतुकों को भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास के बारे में शिक्षित करने और वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की छवि को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- यह परियोजना सागरमाला कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे सार्वजनिक और निजी संस्थानों, संगठनों और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल की भागीदारी के साथ विकसित किया जा रहा है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने भी परियोजना का समर्थन करने के लिए धन का योगदान दिया है।

4. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम

- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को "स्मार्ट सिटी" के रूप में विकसित करना और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना है।

- भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो दुनिया के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास होगा जिससे समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य चालक के रूप में विनिर्माण के साथ भारत में नियोजित शहरीकरण को गति प्रदान करना है।

5. iCET

- iCET की घोषणा भारत और अमेरिका द्वारा की गई थी और इसे दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा चलाया जा रहा है।
- iCET के तहत, दोनों देशों ने सहयोग के छह क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें सह-विकास और सह-उत्पादन शामिल होगा, जिसे धीरे-धीरे क्वाड तक, फिर नाटो तक, उसके बाद यूरोप और बाकी दुनिया तक विस्तारित किया जाएगा।
- iCET के तहत, भारत अपनी मुख्य तकनीकों को अमेरिका के साथ साझा करने के लिए तैयार है और उम्मीद करता है कि वाशिंगटन भी ऐसा ही करेगा।
- इसका उद्देश्य एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और वायरलेस दूरसंचार सहित महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के संबंध में विचार करें:

1. यह एक स्थायी अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण के लिए की गई है।
2. इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना में स्थित है।
3. इसका प्राथमिक लक्ष्य तेल बाजारों को स्थिर करने के लिए तेल उत्पादन को विनियमित करना और अपने सदस्य देशों के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q2. भारत में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और नीति आयोग की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नीति आयोग भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है।
2. एसडीजी इंडिया इंडेक्स एसडीजी प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है।
3. एसडीजी इंडिया इंडेक्स केवल पर्यावरण और आर्थिक संकेतकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को रैंक करता है।
4. नीति आयोग भारत में एसडीजी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2, और 4
D. केवल 1, 3, और 4

Q3. पैंगोंग त्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत तक फैली एक एंडोरहिक झील है
2. इसे पांच उप-झीलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पैंगोंग त्सो, त्सो न्याक, रम त्सो (जुड़वां झीलें) और न्याक त्सो कहा जाता है।
3. यह मीठे पानी की झील है

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2
C. केवल 3
D. इनमे से कोई भी नहीं

Q4. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह आमतौर पर हर पांच साल में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
2. यह सकल घरेलू उत्पाद और गरीबी स्तर जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की समीक्षा करने में मदद करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न 1 न 2

Q5. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और कृषि में इसकी भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
2. नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्यों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।
3. नाबार्ड ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1, 2, और 3
D. केवल 1 और 3

Q6. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसका गठन शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था, जो किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके खिलाफ औपचारिक रूप से जुड़ने की कोशिश नहीं करता था।
2. पहला NAM शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था।
3. NAM के देशों में सामूहिक रूप से वैश्विक आबादी का 50% से अधिक हिस्सा शामिल है।

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q7. भारत के आर्कटिक और अंटार्कटिक मिशनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन, दक्षिण गंगोत्री, 1983 में स्थापित किया।
2. भारत का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) देश की ध्रुवीय अनुसंधान गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
3. भारत आर्कटिक परिषद का सदस्य है और उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
4. भारत के ध्रुवीय मिशनों का प्राथमिक उद्देश्य ध्रुवीय बर्फ की चोटियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1, 2, और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 3, और 4
D. केवल 1, 2, और 4

Q8. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और जीएसटी सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर एक गंतव्य-आधारित कर है।
2. जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करती है।
3. मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर जीएसटी लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q9. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन भूमि और उनके संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है।
2. अधिनियम ग्राम सभा की सहमति के बिना विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति देता है।
3. अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति या परिवार को खेती के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर वन भूमि दी जा सकती है।
4. अधिनियम वन अधिकारों की मान्यता और अधिकार के लिए तीन स्तरीय संरचना की स्थापना का प्रावधान करता है: ग्राम सभा, उप-विभागीय स्तर की समिति और जिला स्तर की समिति।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 1, 3, और 4
C. केवल 1, 2, और 4
D. केवल 2, 3, और 4

Q10. चिल्का झील है

1. एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून।
2. रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित और मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी शामिल है।
3. भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन आश्रय स्थल और पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प C सही है

स्पष्टीकरण

- ओपेक एक स्थायी अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण के लिए की गई है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश शामिल हैं। **अतः, कथन 1 सही है**
- ओपेक का मुख्यालय वास्तव में ऑस्ट्रिया के विएना में स्थित है। यहीं पर संगठन तेल संबंधी नीतियों पर अपनी नियमित बैठकें और चर्चाएं आयोजित करता है। **अतः, कथन 2 सही है**
- ओपेक का प्राथमिक लक्ष्य तेल बाजारों को स्थिर करने और अपने सदस्य देशों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए तेल उत्पादन को विनियमित करना है। ओपेक का लक्ष्य अत्यधिक कीमत में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए तेल की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखना है। **अतः, कथन 3 सही है**

उत्तर : 2 विकल्प C सही है

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है:** नीति आयोग भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है।
- **कथन 2 सही है:** एसडीजी भारत सूचकांक एसडीजी प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है।
- **कथन 3 गलत है:** एसडीजी इंडिया इंडेक्स सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों सहित संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रदर्शन को मापता है।
- **कथन 4 सही है:** नीति आयोग भारत में एसडीजी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है।

उत्तर : 3 विकल्प C सही है

स्पष्टीकरण

- यह पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत तक फैली एक एंडोरहिक झील है **(इस प्रकार कथन 1 सही है)**
- इसे पांच उप-झीलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पैंगोंग त्सो, त्सो न्याक, रम त्सो (जुड़वां झीलें) और न्याक त्सो कहा जाता है (**इस प्रकार कथन** 2 **सही है)**
- खारा पानी होने के बावजूद सर्दियों के दौरान झील पूरी तरह जम जाती है। **(इस प्रकार कथन 3 ग़लत है)**
- इसमें एक ज़मीन से घिरा बेसिन है जो सिंधु नदी बेसिन से एक छोटी सी ऊंची चोटी से अलग है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में यह सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा था।

उत्तर : 4 विकल्प C सही है

स्पष्टीकरण

- हाल ही में, सरकार ने अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच आयोजित अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए।
- यह जीडीपी, गरीबी स्तर और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) सहित महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। **अतः, कथन 2 सही है।**
- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) आमतौर पर हर पांच साल में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित किया जाता है। **अतः, कथन 1 सही है।**
- इसे देश भर के शहरी और ग्रामीण दोनों घरों के उपभोग व्यय पैटर्न पर जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस अभ्यास में एकत्र किए गए आंकड़ों से वस्तुओं (खाद्य और गैर-खाद्य) और सेवाओं पर औसत व्यय का पता चलता है।

उत्तर : 5 विकल्प C सही है

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है:** नाबार्ड की स्थापना 1982 में बी. शिवरामन समिति (कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- **कथन 2 सही है:** नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्यों को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है।
- **कथन 3 सही है:** नाबार्ड विभिन्न वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी समर्थन करता है।

उत्तर : 6 विकल्प C सही है

स्पष्टीकरण

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था, जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र या तटस्थ रहना चाहते थे। **अतः, कथन 1 सही है।**

- समूह की मूल अवधारणा 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया-अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में हुई चर्चा के दौरान उत्पन्न हुई।
- पहला NAM शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था। इसलिए, **कथन 2 सही है।**
- यह तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रूमा, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर और यूगोस्लाव के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज़ टीटो की एक पहल थी।
- NAM के देश संयुक्त राष्ट्र के लगभग दो-तिहाई सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें दुनिया की 55% आबादी शामिल है। **अतः, कथन 3 सही है।**

उत्तर : 7 विकल्प D सही है

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है**: भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन, दक्षिण गंगोत्री, 1983 में स्थापित किया।
- **कथन 2 सही है:** भारत का राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) देश की ध्रुवीय अनुसंधान गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- **कथन 3 गलत है:** भारत आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है; हालाँकि, इसे आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- **कथन 4 सही है:** भारत के ध्रुवीय मिशनों का एक प्राथमिक उद्देश्य ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और संबंधित पर्यावरणीय परिवर्तनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना है।

उत्तर : 8 विकल्प A सही है

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है:** जीएसटी वास्तव में एक गंतव्य-आधारित कर है, जिसका अर्थ है कि कर उस राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है।
- **कथन 2 सही है**: जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है, और यह जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करती है।
- **कथन 3 गलत है:** मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और राज्य सरकारों द्वारा इस पर कर लगाया जाता है।

उत्तर : 9 विकल्प B सही है

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है:** वन अधिकार अधिनियम, 2006, वन-निवास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन भूमि और उनके संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है।
- **कथन 2 गलत है**: अधिनियम में विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन भूमि के किसी भी परिवर्तन से पहले ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता होती है।
- **कथन 3 सही है**: अधिनियम के तहत खेती के लिए किसी व्यक्ति या परिवार को अधिकतम 4 हेक्टेयर वन भूमि दी जा सकती है।
- **कथन 4 सही है:** अधिनियम वन अधिकारों की मान्यता और अधिकार के लिए तीन स्तरीय संरचना प्रदान करता है, जिसमें ग्राम सभा, उप-विभागीय स्तर की समिति और जिला स्तर की समिति शामिल है।

उत्तर : 10 विकल्प C सही है.

स्पष्टीकरण:

चिल्का झील

- चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। अतः, कथन 1 सही है।
- यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, जो रेत की एक छोटी सी पट्टी द्वारा बंगाल की शक्तिशाली खाड़ी से अलग किया गया है।
- 1981 में, चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था (लेकिन यह मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल नहीं है)। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- चिलिका का मुख्य आकर्षण इरावदी डॉल्फ़िन हैं जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप पर देखा जाता है।
- लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किमी में फैले बड़े नलबाना द्वीप (रीड्स का जंगल) को 1987 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन प्रवास स्थल है और पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है। अतः, कथन 3 सही है।
- कालीजाई मंदिर चिल्का झील के एक द्वीप पर स्थित है।

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com